ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 26.7.2017
Page No. 3, Size:(28.97)cms X (8.40)cms.

मनरेगा मजदूरों के खातों को आधार से जोड़ने का अभियान

मनरेगा स्कीम में हो रहे गड़बड़झालों को रोकने के लिए होगा आधार का इस्तेमाल, देशभर में 10 सितंबर तक लगाए जाएंगे कैंप

[रुचिका चित्रवंशी | नई दिल्ली]

सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) से जुड़े सभी मजदूरों को आधार के दायरे में लाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। इसका मकसद इस स्कीम के तहत गड़बड़ियों और डुप्लिकेशन को रोकना है। वित्त मंत्रालय के साथ सलाह कर ग्रामीण विकास मंत्रालय गांवों में कैंप लगाकर इससे लाभार्थियों से उनके बैंक खाते को आधार से लिंक करने के लिए उनकी सहमति मांगेगा।

एक सीनियर अधिकारी ने ईटी को बताया, 'आधार को लिंक करने से लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने में गड़बड़ी को कम करने में मदद मिलेगी...बायो-मीट्रिक वेरिफिकेशन यह पक्का करता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे।' ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अभियान के लिए 13 बैंकों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को तैयार किया है। अब तक नरेगा के तहत 10.7 करोड़ मजदूरों में से 50 फीसदी ने आधार के साथ अपना बैंक एकाउंट लिंक कराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक और सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हमने जहां 85 फीसदी वर्कर्स के लिए आधार सूचना इकट्ठा की थी, वहीं बैंक पहले इसकी सहमति चाहते हैं।'

देशभर में 25 जुलाई से 10 सितंबर के बीच ये कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप के दौरान लाभार्थियों से सहमति फॉर्म हासिल करने के लिए सरकार ने बैंकों, नरेगा अधिकारियों से तय प्रक्रिया को अपनाने को कहा है।

इसके साथ ही, बड़े सफाई अभियान के तहत सरकार नरेगा के तहत फर्जी और इनवैलिड जॉब कार्ड को हटाने का काम कर रही है। फर्जी पाए जाने के बाद तकरीबन 1.12 करोड़ जॉब कार्ड को हटाया जा चुका है। इनमें से 10 लाख वर्कर्स अब नरेगा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी नहीं रखते और उन्होंने अपना जॉब कार्ड सरकार को सरेंडर कर दिया है।

अप्रैल-जुलाई के दौरान इस स्कीम के तहत 86 फीसदी पेमेंट समय पर किया गया है। पेमेंट में देरी इस स्कीम की एक बड़ी कमी मानी जाती है। इस साल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस स्कीम के लिए राज्यों को अप्रैल में 23,443 करोड़ रुपये जारी किए थे, ताकि फंड की दिक्कत नहीं हो। यह रकम कुल बजट के आवंटन का आधा हिस्सा है। राज्यों को इस बाबत बाकी रकम भी सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मिलने की उम्मीद है। सभी राज्यों में लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के लिए मंत्रालय को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) का दायरा बढ़ाने को कहा गया है।